3 पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव

5 अभिनेत्री से सफल नेता बनी स्मृति ईरानी

6 भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इतना बेबस क्यों है?

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 05 प्रति सोमवार, 9 जून 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लंगड़ा और कमजोर घोड़ा तो नहीं बोल गये राहुल गांधी?

नेताओं के साथ बैठक में राहुल ने दिये नेतृत्व में बदलाव के संकेत, जल्द मिल सकता है कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

कमजोर और दिशाहीन नेतृत्व के बीच अपना अस्तित्व खो रही मध्यप्रदेश कांग्रेस में ऊर्जा का संचार करने पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल यात्रा पर पहुंचे। अपनी दो घंटे की इस यात्रा को कांग्रेस नेताओं ने संगठन सृजन अभियान नाम दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि इस बैठक में राहुल गांधी ने न तो पार्टी के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात कही और न ही पार्टी का एजेंडा बताया। (शेष पेज 5 पर)

एक दशक बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा

एक के बाद एक नेताओं से की मुलाकात

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश में 'मिशन-2028' के लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के लिए शुरू किए जा रहे अभियान में शामिल हुए। अभियान शुरू करने से पहले राहुल ने कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की एक बैठक को संबोधित किया और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। इससे पहले, 'संगठन सृजन अभियान' के बारे में जानकारी देते हुए अरुण यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम लंबे समय से राज्य में सत्ता में नहीं हैं और 'मिशन-2028' के तहत हम राज्य में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए काम करेंगे।"

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला सशक्तिकरण के लिये खोला राज्य का खजाना, दी कई सौगातें

-विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सम्मान के मंत्र को आत्मसात कर राज्य में खुशहाली के लिये कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की महिलाओं को खास सौगात दी है। वे निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिये कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के अनुसार महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं के त्याग और समर्पण के बिना कोई भी समाज और राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत में मातृशक्ति की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है और छत्तीसगढ़ सरकार इस परंपरा को और सशक्त कर रही है। कोई भी समाज तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज की महिलाएँ सशक्त न हों। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आने वाले समय में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नए कदम उठाए जाएँगे। महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा सतत जारी रहेगी, क्योंकि नारी शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है।

(विस्तृत पेज 2 पर)

चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है ?

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ''माँ'' पर उगला जुबानी जहर!

(विस्तृत पेज 2 पर)

चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है?

विजय शाह, जगदीश देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा के बाद प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के भी बिगड़े बोल, भाषा की मर्यादा को कर दिया तार-तार

-विजया पाठक

चाल, चरित्र और चेहरे का बखान करने वाली बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है कि प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि पूरी मर्यादाएं तार-तार हो जाती हैं। मप्र के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा का एपिसोड अभी खत्म भी नहीं हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भाषा की मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। प्रेम शुक्ला ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि हम यहां इस मीडिया के प्लेटफार्म पर इसका उल्लेख भी नहीं कर सकते। दुखद है परन्तु यही सत्य है। भाजपा नेता अब अपने असली चाल, चरित्र और चेहरा दिखाने लगे हैं। कल्पना करिये एक नेशनल चैनल की लाइव डिबेट में एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के प्रति इनकी भाषा ऐसी है अन्य जगहों पर इनका रूप क्या होता होगा। विचारणीय है। एक गलीछाप गुंडे की भाषा का प्रयोग करके प्रेम शुक्ला ने दर्शा दिया कि वह किस स्तर के नेता हैं। सत्ता के नशे में चूर नेताओं के बोल बेलगाम हो गये हैं। इन्हें न तो पार्टी की छवि से मतलब है और न ही पार्टी की विचारधारा से। अपने आप को तानाशाह समझने वाले इन नेताओं को पार्टी के पुरोधाओं से जरूर सीख लेनी होगी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी खुद को अमर्यादित नहीं होने दिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, कुशाभाउ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेन्द्र मोदी जैसे समर्पित नेताओं की विचारधारा और सिद्धांतों से पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। जिन्होंने राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति को कभी को अपमानित नहीं होने दिया। लेकिन आज के ये गलीछाप नेता पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को चकनाचूर करने पर तुले हुए हैं। इन नेताओं को नहीं भूलना चाहिए सिद्धांतवादी नेताओं की बदौलत ही ये आज मंच पर बैठने लायक हैं।

संगठन की सीख का बीजेपी के नेताओं पर नहीं हो रहा असर

देश में आरएएस का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसमें कई बुद्धिमान और सहनशील लोग विराजमान हैं। जो समय-समय पर बीजेपी के नेताओं को और सत्तासीनों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। लेकिन लगता है पार्टी के नेताओं को इनकी सीख का कोई असर नहीं हो रहा है। आज भी बीजेपी संगठन के पदाधिकारी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। जो भी अशोभनीय बयान आते हैं वह केवल बीजेपी के नेताओं के ही आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या संगठन और पार्टी दो अलग-अलग धुरी पर चल रही है। जहां एक तरफ मर्यादा है, सहनशीलता है तो दूसरी तरफ अमर्यादित व्यवहार है, बेलगाम बयानबाजी है।

गली छाप नेताओं को प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत?

कुछ दिन बाद मध्यप्रदेश के बीजेपी नेताओं को अपने व्यवहार और बयानबाजी सुधारने के लिए प्रशिक्षण आयोजित होने वाला है। इस प्रशिक्षण में गृहमंत्री अमित शाह समझायेंगे कि नेताओं को कैसा व्यवहार करना है, कैसी बयानबाजी करना है। वगैरह-वगैरह। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बीजेपी सत्ता की इतनी लालची हो गई है कि वह इन गलीछाप गुंडों की भाषा का प्रयोग करने वालों को सुधारने में लग गई है? क्या पार्टी में आज अच्छे नेताओं की कमी हो गई है कि इन्हें होना पड़ रहा है? क्या पद पर बिठाने के पहले इनके चाल, चरित्र और चेहरे को नहीं देखा गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं।

प्रेम शुक्ला द्वारा की गई किसी की मां पर टिप्पणी माफी लायक नहीं

एक डिबेट में प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मां पर जो टिप्पणी की है वह कतई ही माफी लायक नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर तो मर्डर तक हो जाते हैं। मां किसी की भी हो वह मां होती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी है वह गलीछाप गुंडा ही कर सकता है। लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शुक्ला को तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जो अन्य नेताओं के लिए भी एक सबक हो।

मोदी और शाह ने क्यों साधी चुप्पी?

आश्चर्य करने वाली बात यह है कि देश की सेना पर जगदीश देवड़ा, विजय शाह द्वारा दिये गये बयान पर अब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोई बयान नहीं आया है। तीनों की चुप्पी इस बात की ओर इशारा तो नहीं करती कि इससे आने वाले समय में पार्टी पर कोई बड़ा संकट आ जाये। क्योंकि मंत्रियों के बड़बोलेपन से जुड़े बयान देने पर यह कहीं न कहीं सरकार का अपने मंत्रियों के ऊपर अनियंत्रण के संकेत देता है।

सवाल बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर उठ रहे

खुद को सशक्त देशभक्ति पार्टी के रूप में देश में झंडे बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं के बेतुके बयानों से न सिर्फ प्रदेश भाजपा बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं भी परेशान हैं।

विजय शाह पर अभी तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी

विजय शाह के बयान से न सिर्फ पूरे देश में गुस्सा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश तक खुद नाराज हैं। यही कारण है कि शाह पर एफआईआर दर्ज करने से लेकर उन्हें बर्खास्त करने तक की कार्यवाही के निर्देश कोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन को दिये। कुल मिलाकर विजय शाह का खौफ भाजपा नेताओं में ऐसा है कि कोई नेता उनसे इस विषय पर बात नहीं कर रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला सशक्तिकरण के लिये खोला राज्य का खजाना, दी कई सौगातें

(पेज 1 का शेष)

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला कल्याण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत पिछले 13 महीनों से प्रति माह 1,000 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित कर रही है। अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 8,488 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से उनका मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

चार नए पोर्टल और डिजिटल पहल की लॉन्चिंग

उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत किया जिसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पोर्टल, इंद्रा पोर्टल तथा स्थापना पोर्टल शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए नए अवसर

महिला मड़ई में लगे स्टॉल्स के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब तक 15 से 20 लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री हो चुकी है, जो महिला उद्यमिता को दर्शाता है। उन्होंने घोषणा की कि नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से "यूनिटी मॉल" बनाया जाएगा, जहाँ महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बेचने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन किया और बताया कि छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब इस सेंटर के व्यवस्थित संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल एक नारा नहीं, बल्कि अपनी नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के राज्य बजट में महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को सशक्त किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है।पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अब विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण का लाभ जल्द ही महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएँ राजनीति से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने और रेल संचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

40 महिला पिंक ई-ऑटो लेकर चलेंगी

नवा रायपुर में अब 40 महिला पिंक ई-ऑटो लेकर चलेंगी। इससे नवा रायपुर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का सफर आसान होगा। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल ई-ऑटो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह सेवा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के सहयोग से शुरू की गई है। ई-ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। इसमें 3 क्लस्टरों के 15 ग्राम संगठनों की कुल 40 महिला सदस्य शामिल हैं। यह ई-ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। 'लखपति दीदी योजना' के तहत यह पहल 40 महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। यह सेवा आने वाले समय में स्थानीय परिवहन के क्षेत्र में एक मॉडल बनकर उभरेगी, जिससे नवा रायपुर के निवासियों को सुविधाजनक, किफायती और प्रदूषण रहित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री साय कांकेर में बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव में हुए शामिल

पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव हैः मुख्यमंत्री साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर जिले के संबलपुर हाई स्कूल कराटी में आयोजित दो दिवसीय बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारे पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की। यह महोत्सव क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण आयोजन है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ादेव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर और दुर्गुकोंदल में गोंड़वाना समाज के भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपये, गोंड़वाना समाज के 12 परगना में शेड निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये, 5 सर्कल में शेड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये, ग्राम पंचायत संबलपुर के भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 3 लाख लोगों को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गृह प्रवेश भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, तेंदूपत्ता बोनस योजना, सुशासन तिहार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, पीएम जनमन योजना तथा होम स्टे योजना जैसे अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले जा चुके हैं। आगामी समय में हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे।

वर्षा से पूर्व बाढ़ नियंत्रण के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें: सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बाढ़ एवं आपदा प्रबन्धन से संबंधित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ की स्थिति में विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित कार्य योजना तैयार कर लें। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के सीईओ व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नालों व पुल पुलियों की सफाई कराने के निर्देश दिये ताकि अतिवर्षा की स्थिति में नालों व पुल पुलियों में वर्षा का पानी ओवरफ्लो होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन की खण्ड स्तरीय समिति की बैठक लेकर वर्षा से पूर्व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर लें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि बाढ़ राहत के लिये आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की भी एसडीएम समीक्षा करें। यदि कोई कमी हो तो उसकी डिमाण्ड जिला कार्यालय को भिजवाएं ताकि पूर्ति की जा सके। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा व संजीव नागू सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

कुनकुरी-रनपुर मार्ग पर ईब नदी पर बनेगा उच्चस्तरीय पुल

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जशपुर जिले में विकास के कार्य तेजी से संचालित हो रहे हैं। इससे जिले की तस्वीर बदलने लगी है। अधोसंरचना निर्माण कार्यों की लगातार मिल रही स्वीकृति और निर्माण कार्यों में गति पकड़ने से सुदूर अंचल मुख्य पहुंच मार्ग से जुड़ने लगे है। इससे विकास कार्यों को संचालित करने में आसानी हो रही है। इसी कड़ी में जशपुर के कुनकुरी-रनपुर मार्ग पर ईब नदी पर 120 मीटर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। 4 करोड़, 86 लाख, 85 हजार की लागत से बनने वाली इस पुल के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस पुल के बन जाने से आसपास के 8 गांवों के 10,500 से अधिक निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को बरसात के दिनों में हो रही असुविधा से मुक्ति मिलेगी और विकासकार्यों को गति मिलेगी। शासकीय योजनाएं भी बरसात के दिनों में आसानी से संचालित हो सकेगी। पुल के निर्माण होने से बरसात के मौसम में छात्र आसानी से स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे। आपात स्थिति में एम्बुलेंस की पहुंच आसान होगी। इससे मरीजों को समय पर इलाज हो सकेगा। किसानों द्वारा उत्पादित फसल बरसात के दिनों में भी आसानी से बाजार तक पहुंच पाएगी और नदी की तेज बहाव भी राशन सामग्री और अन्य जरूरत की चीजें की पहुंच पर बाधा नहीं बनेगी।

अनुविभाग, तहसील तथा विकासखण्ड स्तर तक ई- ऑफिस सिस्टम का क्रियान्वयन हो- कृष्ण गोपाल तिवारी, कमिश्नर

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने अनु विभाग, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर ई- ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि अभी जिला स्तर पर स्थित सभी विभाग में ही ई-ऑफिस सिस्टम के तहत कार्य किया जा रहा है। अब ई- ऑफिस सिस्टम नीचे अनु विभाग एवं तहसील तथा विकासखंड स्तर पर भी लागू किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में जितने भी लीज एक्सपायर हुए हैं उन सभी लीज का नवीनीकरण राजस्व विभाग प्राथमिकता से करे और लीज नवीनीकरण को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कराए साथ ही राजस्व विभाग यह भी बताएं कि कितने लीज नवीनीकरण से शेष रह गए हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए की संबंधित व्यक्ति से आवेदन लेकर लीज नवीनीकरण की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए और यदि संबंधित व्यक्ति को लीज नवीनीकरण के बारे में नहीं मालूम है तो राजस्व विभाग स्वत उस व्यक्ति का लीज नवीनीकरण करें। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व विभाग का यह प्रमुख दायित्व है कि वह लोगों को लीज नवीनीकरण के लिए प्रेरित करें और उनसे लीज नवीनीकरण के आवेदन ले। आवेदन लेकर लीज नवीनीकरण की कार्रवाई करें।कमिश्नर ने वन व्यवस्थापन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि वन व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर प्राथमिकता से दर्ज हो जाने चाहिए। जो केस गुम गए हैं या गायब हो गए हैं ऐसे प्रकरण को भी प्राथमिकता से ढूंढ कर उसे आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ऑनलाइन तथा उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर ऑफलाइन उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन जैसी चुनौतियों से परेशान विश्व

आज जब समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों और समर्पित नेतृत्व के बल पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैश्विक उदाहरण बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को न केवल नीति निर्माण में प्राथमिकता दी है, बल्कि इसे जन-आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर यह समीचीन है कि हम भारत की पर्यावरणीय उपलब्धियों का पुनरावलोकन करें और जानें कि कैसे भारत 'विकास' और 'पर्यावरणीय संतुलन' के बीच सामंजस्य स्थापित कर रहा है। भारत की आध्यात्मिकता हमेशा से प्रकृति के संरक्षण की पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने उद्बोधनों में बार-बार यह दोहराया है कि "पर्यावरण हमारे लिए कोई बाहरी विषय नहीं, बल्कि आस्था का विषय है।" उन्होंने 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करके एक वैश्विक विचार प्रस्तुत किया कि जब तक जीवनशैली में बदलाव नहीं होगा, तब तक जलवायु संकट का समाधान संभव नहीं।

यह अभियान भारत की पारंपरिक जीवन शैली, जिसमें संयम, पुनर्चक्रण और सह-अस्तित्व शामिल है, को आधुनिक दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत यह अभियान अब वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। यह व्यक्तिगत और स्वप्रेरणादायक जीवनशैली में परिवर्तन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश है। भारत के लाखों लोगों ने इस मिशन में भागीदारी की है, जिससे पौधारोपण के साथ उसका संरक्षण, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) में 40% तक की कमी लाना है। इसके तहत वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार, हरित पट्टियों का विकास और स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है। इससे लाखों टन प्लास्टिक कचरे में कमी आई है और स्वच्छता मिशन को भी मजबूती मिली है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत, पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियाँ करने वालों को 'ग्रीन क्रेडिट' दिए जाते हैं, जिन्हें दूसरे पर्यावरणीय दायित्वों की पूर्ति में उपयोग किया जा सकता है। इससे व्यक्तिगत, संस्थागत और औद्योगिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है। 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर के वितरण से लाखों परिवारों को धुएं से मुक्ति मिली, जिससे इनडोर वायु प्रदूषण में भारी कमी आई। 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME)' योजना के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे भारत शहरी प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की ओर अग्रसर हुआ है। भारत ने 2030 तक वन क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'कैंपेन फॉर ग्रीन इंडिया', 'राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन', और अमृत सरोवर योजना जैसे अभियानों के माध्यम से न केवल वनों का विस्तार हो रहा है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र भी पुनर्जीवित हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के वन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।

सियासी गहमागहमी

भाजपा को भी क्या दिन देखने पड़ गए?

एक के बाद एक भाजपा नेताओं और मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद अब प्रदेश और शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने न चाहते हुए भी अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह प्रशिक्षण आगामी 12 से 14 जून को पचमढ़ी में दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में एक केबिनेट स्तर के मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने प्रशिक्षण पचमढ़ी में कराए जाने का अनुरोध किया था। जिसे स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट समाप्त होने के बाद तुरन्त बाद नेताओं को प्रशिक्षण देने की तारीख घोषित की। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस प्रशिक्षण में बतौर विशेषज्ञ कौन से नेता शामिल होते हैं जो विधायक, मंत्री और सांसदों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे।

कभी भी जारी हो सकती है ट्रांसफर सूची

मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही प्रशासनिक अमले में फेरबदल करने जा रही है। गृह विभाग द्वारा हाल में किए गए आईपीएस तबादलों के बाद अब आईएएस अधिकारियों के तबादलों की तैयारी अंतिम चरण में है। यह बदलाव मंत्रालय स्तर से लेकर जिलों तक देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक कर तबादलों की सूची को अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बड़े पैमाने पर फेरबदल के मूड में नहीं हैं, लेकिन जिन पदों पर नियुक्तियां बेहद जरूरी हैं, वहां बदलाव जल्द किए जाएंगे। सचिव स्तर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में भी फेरबदल संभव है। यही नहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी नवीन पदस्थापना की जा सकती है, खासकर उन जिलों में जहां प्रशासनिक गति प्रभावित है या कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

एक MMS से - डॉ. मनमोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में UPA ने मनरेगा दिया, जिससे करोड़ों गरीबों को रोजगार और सम्मान मिला।

और दूसरा MMS है - Modi Monitoring System, जो गरीब मजदूरों और बहनों से उनका मेहनताना तक छीन रहा है।

ये सिर्फ शोषण नहीं, ये अपमान है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन एक संगठित घोटाले का स्वरूप ले चुका है। जाहिर है सरकार में नीचे से ऊपर तक सुनियोजित संरक्षण के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। प्रदेश में सार्वजनिक संसाधनों की यह लूट भाजपा के कुशासन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। भाजपा का भ्रष्टाचार प्रदेश को खोखला करता जा रहा है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

अभिनेत्री से नेता बनी स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री तक का तय किया सफर

समता पाठक/जगत प्रवाह

अभिनेत्री से नेता बनी स्मृति ईरानी वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ है। स्मृति ईरानी ने टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में लीड रोल के जरिए अभिनय जीवन की शुरुआत की थी। स्मृति ईरानी ने 2003 में भाजपा का दामन थामा था। उन्हें एक स्पष्ट नेता के तौर पर पहचान मिली है। वह अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षा ग्रहण की। वह अपनी सुंदरता की वजह से कई प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। वह मिस इंडिया प्रतियोगिता की प्रतिभागी भी बनीं। उनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षशील रहा है। उन्होंने काफी संघर्षों के बाद मॉडलिंग, अभिनय और राजनीति की दुनिया में प्रसिद्धि हासिल की हैं।स्मृति ईरानी ने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने समाज की सारी बंदिशें तोड़कर ग्लैमर जगत में कदम रखा। स्मृति ईरानी ने 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वह जीत नहीं सकी थी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने मायानगरी मुंबई में अपनी किस्मत आजमाई।

स्मृति ईरानी ने अभिनय के क्षेत्र में मॉडलिंग से अपने जीवन की शुरुआत की। वह वर्ष 1998 में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची, लेकिन मिस इंडिया नहीं बन पाई थी। स्मृति ईरानी ने वर्ष 2000 में टेलीविजन सीरियल 'हम है कल आज कल और कल' के साथ अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि, उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल के जरिए प्रसिद्धि हासिल की, क्योंकि इस सीरियल में वह लीड रोल 'तुलसी' की भूमिका में थी। स्मृति ईरानी अपने अभिनय कौशल के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड और स्टार परिवार पुरस्कार जीत चुकी हैं। वर्ष 2001 में स्मृति ईरानी ने जीटीवी पर प्रसारित रमायण में सीता की भूमिका निभाई थी। वर्ष 2006 में उन्होंने 'थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान' टीवी सीरियल में सह निदेशक के रूप में कार्य की थीं। वर्ष 2008 में उन्होंने डांस पर आधारित टीवी सीरियल 'ये हैं जलवा' को साथी तंवर के साथ होस्ट किया था।

स्मृति ईरानी ने अपने जीवन की शुरुआत तो एक अभिनेत्री के रूप में की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें नेतानगरी पहुंचा दिया। स्मृति ईरानी ने टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के जरिए लोगों के बीच काफी प्रसिद्धि पाई। इसके बाद, स्मृति ईरानी 2003 में भाजपा में शामिल हुई। स्मृति ईरानी को सबसे पहले महाराष्ट्र में भाजपा के यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद, वर्ष 2004 में स्मृति ईरानी दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन वह हार गई थीं। साल 2014 में वह अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी, लेकिन इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वह लोगों के बीच जाती रहीं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी सीट से मात दी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी वर्ष 2011 और 2017 में गुजरात से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं।

स्मृति ईरानी मई 2014 से जुलाई 2016 तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा मंत्रालय) मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके बाद, उन्हें जुलाई 2017 से मई 2018 तक सूचना और प्रसारण मंत्री का जिम्मा मिला। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई 2016 से जुलाई 2021 तक कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया है। स्मृति ईरानी ने शिक्षा मंत्री के रूप में अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की। वह भारत की नई शिक्षा नीति की कल्पना करने में सहायक थीं और भारत के पहले MOOC प्लेटफॉर्म SWAYAM, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और GIAN नामक शिक्षाविदों के वैश्विक नेटवर्क सहित कई बड़े पैमाने की परियोजनाओं की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने छात्रों और शिक्षाविदों के बीच अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईएम-प्रिंट लॉन्च किया। कोविड-19 महामारी के दौरान कपड़ा मंत्री के रूप में, वह वैश्विक लॉकडाउन के बीच तीन महीने की अवधि में भारत को पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों को प्रेरित करने में सफल रहीं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में, स्मृति ईरानी ने उन्नत कपड़ा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन दिया, जिसमें महत्वपूर्ण तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण एचएसएन कोड अधिसूचित करना का उनका प्रयास शामिल था।

कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लंगड़ा और कमजोर घोड़ा तो नहीं बोल गये राहुल गांधी?

(पेज 1 का शेष)

कुल मिलाकर पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कटाक्ष किया। समझ ही नहीं आया कि यह राहुल की सृजन अभियान की यात्रा थी या फिर संसद का हॉल जहां वे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की बखिया उधेड़ने में लगे थे। खैर, राजनीति के अपने दांव-पेंच होते हैं जिसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राहुल गांधी की यह भोपाल यात्रा कई मायनें में महत्वपूर्ण थी। खासतौर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर आये और जनता को उनसे एक बदलाव के संचार की आशंका थी। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।

10 साल बाद भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे राहुल गांधी

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी एक दशक बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने दफ्तर के बाहर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि दी। इसके बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। हालांकि भोपाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार समेत कई नेता पहुंचे हुए थे।

भोपाल में क्यों खास है राहुल गांधी का दौरा

विश्लेषकों के अनुसार राहुल के भोपाल दौरे को कांग्रेस के लिए "संगठनात्मक नवचेतना" का प्रतीक माना जा रहा है। उनका दौरा पुराने समर्पित नेताओं को अहमियत और निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी का संकेत भी है। उनका पूरा फोकस मौजूदा स्थिति समझाकर एमपी में पार्टी को आगे ले जाना है। राहुल गांधी का यह दौरा इसलिए भी खास है कि 3 दिन पहले 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक विशाल महिला महासम्मेलन को संबोधित किया था। इसके जवाब में राहुल भोपाल पहुंचे हैं।

अपने कार्यकर्ताओं को हत्सोहाति करने वाला बयान

बैठक में राहुल गांधी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को लगड़ा घोड़ा बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी-कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और कभी-कभी बारात के घोड़े को रेस में भेज देती है ये कमलनाथ ने भी कहा है हमें ये छांटना है कि बारात का घोड़ा बारात में जाए, रेस का घोड़ा रेस में और लंगड़ा घोड़ा आराम करे।

गुटबाजी में घिर रही कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि ये क्षेत्रीय नेताओं की पार्टी है। राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का कहना है कि कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों की मौजूदगी बीते दो दशकों से सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है। विश्लेषकों के अनुसार "कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों से निपटना आसान नहीं है। राहुल गांधी के एक बार के मध्य प्रदेश दौरे से बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात यह कि नए लोगों को आप लेकर आएंगे ये सही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि नए लोग इन्हीं क्षत्रपों के प्रभाव में नहीं आएंगे? इससे बचाने के लिए पार्टी क्या कदम उठाएगी?"

अनुशासन की कमी का गंभीर संकेत

जबलपुर के बाद अब भोपाल में कांग्रेस नेताओं के पोस्टर वार केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस में गहरे अनुशासन की कमी और गुटीय विभाजन का प्रतीक बनकर सामने आया है। विभिन्न गुटों द्वारा अपने नेताओं को प्रमुखता देने और दूसरों को दरकिनार करने का यह चलन दिखाता है कि पार्टी के भीतर एक मजबूत, केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव है जो सभी को एकजुट कर सके। यह न केवल आम जनता के बीच गलत संदेश देता है बल्कि 'संगठन सृजन अभियान' की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। जब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से गुटबाजी दिखाते हैं, तो यह सीधे तौर पर मतदाताओं के विश्वास को कम करता है और उन्हें पार्टी से दूर कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ लेते ही मुख्यतः तीन प्रकार की नीतियों पर दिया जोर

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता,
विचारक और
समाजवादी नेता

अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालना, उनके दृष्टिकोण से अमेरिका के आंतरिक वातावरण को बदलने पर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ऋण से उबार कर पटरी पर लाने का, उनके द्वारा लिए ये तीनों ही निर्णय अमेरिका के बाहर की दुनिया के लिए विवादास्पद हैं। मानवता, धर्मनिरपेक्षता आदि तर्कों के आधार पर आलोचना के बिन्दु हैं। परंतु अपने स्वभाव के मुताबिक ट्रम्प अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ नजर आते हैं और उनमें कोई विशेष बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती। मैं समझता हूं कि ट्रम्प अब वैश्विक आर्थिक नीतियों के मार्ग से बगैर कहे अमेरिका को हटाना चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन को भी अगर स्थायी तौर पर नहीं तो कम से कम वक्ती तौर पर निष्प्रभावी रखना चाहते हैं। वे अब अमरीका को अमेरिकी राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाना चाहते हैं। पिछले करीब चार पांच दशकों में अमेरिका ने जो दुनिया के साहूकार और मददगार बनने की पूंजीवादी शैली की नीति बनाई थी उससे वे हटना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका के बाहर के देशों को जो आर्थिक सामरिक मदद अमेरिका दे रहा था उसे लगभग समाप्ति की ओर ला दिया है।

जिन कुछ देशों को वे अभी भी मदद दे रहे हैं वह भी वे उनके वैदेशिक कूटनीति, अमेरिका के सामरिक राजनीतिक हितों के आधार पर तय कर रहे हैं। मेरी सूचनाओं के अनुसार आम अमरीकी उनके इन प्रयासों से संतुष्ट और सहमत है। यद्यपि वहां की विरोधी पार्टी ने उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में एक दिवसीय प्रदर्शन किया था, परंतु अमेरिकी समाज की ओर से उन्हें कोई विशेष समर्थन नहीं मिला।

अमेरिका की विदेश नीति के निम्न नये सूत्र हैं -

1) अमेरिका की आर्थिक, सामरिक श्रेष्ठता को वापस लाना

2) चीन के विस्तार को नियंत्रित करना

3) चीन की आर्थिक शक्ति को सीमित करना

पिछले दिनों अमेरिका चीन के बीच खुले व्यापार के शुरू होने के बाद चीन अमरीका के लिए सबसे बड़ा निर्यातक था।

चीनी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ पहुंचा था।

ट्रम्प ने आरम्भ में उन सभी देशों से आयात पर टैरिफ बढ़ाया जो अमेरिकी आयात पर टैरिफ ज्यादा लगाते हैं और अमेरिका उन्हें निर्यात में अधिक छूट देता है। उन्होंने उन सभी देशों पर इसी आधार पर टैरिफ बढ़ाया कि जितना टैरिफ अमेरिका अपने निर्यात में चुकायेगा उतना ही आयात में वसूल करेगा। ट्रम्प की इस घोषणा के बाद और टैरिफ वार शुरू करने के बाद समूची दुनिया में हलचल होना स्वाभाविक थी तथा चीन सहित कई देशों ने भी आरंभ में बदले में उसी रफ्तार से टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। ट्रम्प ने उसी भाषा में उत्तर दिया। चीन ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की घोषणा के आधार पर अमेरिकी आयात पर टैरिफ बढ़ाया गया तथा उसे बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया । बदले में 16 अप्रैल को अमेरिका ने चीनी आयात पर टैरिफ दर 145 प्रतिशत से बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया। मीडिया ने इसे टैरिफ वार का नाम दिया है। परंतु मेरी राय में यह टैरिफ ब्लैकमेलिंग है। अमरीका कई प्रकार के अघोषित लाभ , सुविधाएं, राजनीतिक समर्थन और अपने लक्ष्य के विरोधी देशों की घेराबंदी से दबाकर उनसे सहयोग लेना चाहता है। अमेरिका के चीन पर शुल्क की बढ़ोत्तरी के बाद प्रारंभिक तौर पर चीन को फायदा नजर आया और अप्रैल के दस ग्यारह तारीख तक चीन का निर्यात 12.4 प्रतिशत बढ़ा तथा आयात में 4.3 प्रतिशत की कमी आई, क्यों कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन के निर्यात की दिशा भी बदली और चीन ने अमेरिका को छोड़कर दूसरे कम आर्थिक शक्तियों वाले देशों को सस्ता निर्यात शुरू कर दिया। परंतु, इसका प्रभाव अमेरिका पर विशेष नहीं पड़ा क्योंकि अमेरिका चीन से जो आयात करता है वह अधिकांश उपभोक्ता सामग्रियां है, जो बुनियादी आवश्यकता नहीं हैं। परंतु वह वक्री है। वस्तुतः दरअसल चीनी उपभोक्ता माल का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका में ही था। भले ही तकनीकी रूप से चीन का अमेरिकी आयात घटा हो और अब देशों को निर्यात बढ़ा हो, इसका नुकसान चीन को हो रहा है। जनवरी-मार्च 2025 के बीच चीनी निर्यात 5.8 प्रतिशत बढ़ा और आयात में 07 प्रतिशत की गिरावट आई। यानी चीन का अमेरिका के साथ व्यापार में जो व्यापार घाटा 27.6 अरब डॉलर था, टैरिफ वृद्धि के बाद यह घाटा बढ़ कर 76. 6अरब डालर हो गया। मतलब साफ है कि चीनी माल के अमेरिकी बाजार में जाने की कमी होने के बाद चीन को व्यापार अधिशेष में लगभग 50 अरब डॉलर याने लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जिन दूसरे देशों ने चीन से कुछ आयात बढ़ाया है उनसे चीन का माल तो बिकेगा परंतु चीन को कोई विशेष मुनाफा नहीं होगा। जैसे भारत चीन से तेल आयात करता है, जेम-ज्वेलरी आयात करता है, वियतनाम से मोती , ताइवान से इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टीवी, साउंड रिकार्डर, स्विट्जरलैंड से मैकेनिकल सामा, थाइलैंड से तेल और वसा आयात करता है। अब यह आयात चीन अपने पुराने टैरिफ दरों पर भारत या अन्य देशों को निर्यात करता रहेगा। ताइवान, वियतनाम, थाइलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देश भारत या अन्य देशों को निर्यात करते रहेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था कुछ दिनों में प्रभावित होगी। अमेरिका को तो एक अर्थ में यह फायदा ही हुआ है कि अमेरिकीयों ने मूल्यवृद्धि की आशंका से स्वतरू अपनी खरीददारी में पहले माह में 10-20 प्रतिशत और बाद के माहों में बीस से चालीस प्रतिशत विदेशी सामान की खरीद कम कर दी। अमेरिकी कंपनियों का अपना घरेलू बाजार बढ़ गया है। यहां तक कि खरीददारी का मौसम भी बदल गया। अमेरिकी लोग पिछले दस वर्षों से सितंबर माह के आरंभ में एप्पल फोन आदि खरीदते थे क्योंकि एप्पल सितंबर में नये माडल पेश करता था। अब अप्रैल में ही यह खरीदी हो गई है। अमेरिका के स्टोर्स पर खरीददारों की भीड़ है। अमरीका ने योजना के तहत 14 अप्रैल को चीन के अलावा अन्य देशों को बढ़ाये हुए टैरिफ पर नब्बे दिनी रोक लगा दी। चीन से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी छूट दे दी। अमेरिका की जो जरूरतें फिलहाल बाहर के बाजार से सस्ती दरों पर पूरी हो रही थीं उन्हें एक प्रकार से जारी रखा है। अमेरिकी स्टोर मालिक इन सामानों को बड़े पैमाने पर आयात कर अपने स्टोरों में भर रहे हैं, जिससे दोबारा टैरिफ वृद्धि हुई तो अमेरिकी उपभोक्ता को लम्बे समय तक विदेशी आयात की निर्भरता नहीं रहे। स्थिति यह है कि क्रिसमस की खरीददारी लोग आठ माह पहले कर रहे हैं। 2 से 7 अप्रैल के बीच डिब्बाबंद सामान, सब्जी, इंस्टेंट काफी, केचप आदि की खरीद 25 प्रतिशत बढ़ गई है। यह भी अमेरिका को एक प्रकार का फायदा ही है। अगर अमेरिकी समाज अपने उपभोक्ता खर्च को कम करेगा तो विदेशी आयात घटेगा और स्वदेशी की मांग बढ़ेगी।

अमेरिकी शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद भारत में निवेशकों की सम्पत्ति लगभग 11. 5 लाख करोड़ रुपए घटने का अनुमान लगाया गया है। इससे भारत के निवेशक और कुछ राजनेता चिंतित हैं। भारत की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 11. 5 लाख करोड़ रुपए से घटकर 4 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। हालांकि इस उतार से अभी तक भारत के बाजार में हलचल नहीं है। दरअसल यह घट-बढ़ बहुत हद तक प्रतीकात्मक और काल्पनिक होती है। जैसे एक समय टू-जी स्पेक्ट्रम की खबरें छपने के बाद दो लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा बताया गया था जो एक प्रकार से इमेजनरी था। इस खबर ने देश में उस समय बड़ी हलचल पैदा की। इससे केन्द्र की सरकार बदल गई। बाद में टू-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी और भी कम दरों पर हुई। इसका मतलब है कि या तो भारत के निवेशक इतने परिपक्व हो चुके हैं कि वे इन खबरों और इस काल्पनिक उतार चढ़ाव से अब प्रभावित नहीं होते। वैसे भी मेरी राय में भारत के निवेशकों को घबड़ाकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब किसी देश के बाजार में, विशेषकर शेयर बाजार में घाटा होता है, शेयर के दाम गिरते हैं, घबड़ाकर निवेशक शेयर सस्ते दामों पर बेचते हैं तब दुनिया के पूंजीपति भारत के व उन देशों के गिरावट वाले शेयर को खरीदते हैं। कोरोना काल में भी यह खेल देख चुके हैं। यह विदेशी पूंजीवाद के द्वारा भारतीय पूंजी का चालाक अधिग्रहण होता है। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका की टैरिफ वृद्धि से वर्ष 2025 में अमेरिका का निर्यात 85 हजार करोड़ रुपए कम हो सकता है। इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। भारत का अमरीका को निर्यात बुनियादी जरूरतों की चीजों पर नहीं होता। ज्यादातर खानपान उपभोक्ता सामग्री या अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भारत में निर्मित किए गए सामान के निर्यात पर ही होता है। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में स्वतरू यह स्वीकार किया गया है कि दुनियाभर में निर्यात 1.3 प्रतिशत कम होगा। परंतु भारत का निर्यात या भारत की जीडीपी में 0. 2 प्रतिशत की कमी होगी। रुपयों में केवल 66 हजार करोड़ की कमी होगी। इस कमी को भारत अपने देश के भीतर स्वदेशी के उपयोग, विदेशी उपभोक्ता सामग्री को कम कर आसानी से पूरा कर सकता है।

आज देश में केवल सौन्दर्य प्रसाधन का व्यापार दस लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। महानगर, शहर से लेकर कस्बों तक में न केवल दूल्हा-दुल्हन बल्कि मध्यवर्गीय लोग तक सुन्दर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं। स्वस्थ होने या वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी के नये उभरते व्यापार केन्द्रों में जा रहे हैं। इन नेचुरोपैथी सेंटर में जल-जमीन-जंगल पर्यावरण तो स्वदेशी होता है, जो व्यापारियों की लाचारी है। जंगल या नदियां आयात नहीं किए जा सकते। परंतु इनकी मशीनें, जिम की मशीनें, शैम्पू, लोशन विदेश से आयात हो रहे हैं। अगर हम भारतीय परम्परा पर वापस लौट आयें और साल छह माह घर में ही हलदी तेल का उबटन शुरू कर दें तो छह सात लाख करोड़ रुपए बच सकता है। विदेशी शैम्पू तेल निर्माताओं का मुनाफा कई हजार करोड़ रुपए कम हो सकता है। इस छोटे से निर्णय से भारत 66 हजार करोड़ रुपए के घाटे को पूरा कर सकता है। और कुछ बचा भी सकता है। दुखद यह है कि भारत की सत्ता व राजनीति दिमागी तौर पर विदेशी पूंजी, विदेशी सभ्यता व गोरी चमड़ी की मानसिक गुलाम हो गयी है। आइये, हम सब मिलकर गांधी के स्वदेशी, स्वावलंबन व स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनायें। लोहिया के भारतीय भाषा-भूषा-भवन के सिद्धांत को अपनायें तो टैरिफ वार का यह संकट तिनके के समान उड़ जायेगा। भारत की सत्ता गांधी का नाम नहीं ले सकती और प्रतिपक्ष गांधी को वोट का हथियार तो बनाता है परंतु अमल में नहीं लाता।

सरकारी आतंकवाद बनाम सरकारी सुशासनवाद

किशन भावनानी
एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर दुनियाँ का हर देश आज आतंकवाद और भ्रष्टाचार के दंश से पीड़ित है परंतु अनेक देशों में तो आतंकवादी भ्रष्टाचार किसी एकल इकाई तक अब सीमित नहीं रहा वह टॉपअप से बॉटमअप तक या यूं कहें कि शासन वाया प्रशासन वाया दलालों (जासूसों) के माध्यम से भ्रष्टाचार आतंकवाद का प्रचलन अति बढ़ गया है, जो अक्सर हम 40-50 पर्सेंट लिफाफा के रूप में सुनते आ रहे हैं, यानें 1 रूपया निकलता है तो 15 पैसा लाभार्थी के हाथ में आता है, हालांकि आज भले ही कम स्तर पर हो परंतु है जरूर! इस तरह से आतंकवाद एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता बल्कि उसके पीछे पूरी चैनल जुड़ी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 200 से अधिक देशों ने मिलकर एक ऐसी ट्रिटी या व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें ऐसे देशों को आतंकवादी देश घोषित करें जो सरकारी आतंकवाद की परिभाषा में आता हो व पारदर्शी व स्वच्छ तथा अच्छे प्रशासन वाले देश की सरकारों को सरकारी सुशासन वाला देश से नवाजा जाए जिनकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत-पाक तनाव में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने देखा कि किस तरह मारे गए आतंकवादियों को पड़ोसी मुल्क ने अपने राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर सलामी देकर उनको ख़ाक ए सुपुर्द, किया इस वाक्यात को पूरे विश्व ने देखा इसे कुछ लोगों ने सरकारी आतंकवाद की संज्ञा दी। वैसे ही भ्रष्टाचार भी शासन प्रशासन दलालों के गठजोड़ में भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 40 50 पेर्सेंट लिफाफे की शुभ सुगबुगाहट इलेक्शन के दिनों में होते रहतो है,इसलिए मेरा मानना है कि इन दोनों परिस्थितियों याने सरकारी आतंकवाद व भ्रष्टाचार को सभी देशों ने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानूनों में एक धारा जोड़कर सरकारी आतंकवाद का संज्ञान लिया जाए।चूँकि शासन प्रशासन दलालों का मेल, सरकारी आतंकवाद का खेल। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, सरकारी आतंकवाद बनाम सरकारी सुशासनवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों ना हरदेश में शासन प्रशासन और दलालों के गठजोड़ से किया गया भ्रष्टाचार व आतंकवाद में जमानत न होकर ट्रायल के बाद सीधा एक्विट्टल या सजा हो?

बात अगर हम सरकारी आतंकवाद को समझने की करें तो, सरकारी आतंकवाद और सरकारी सुशासन वाद में काफी अंतर है। सरकारी आतंकवाद में सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों या अन्य देशों के नागरिकों पर हिंसक और गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई करना शामिल होता है, जबकि सरकारी सुशासनवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी के साथ काम करती है।

बात अगर हम सरकारी सुशासनवाद को समझने की करें तो, सुशासन क्या है?शासन का तात्पर्य शासन की सभी प्रक्रियाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और प्रथाओं से है, जिनके माध्यम से आम चिंता के मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है और उन्हें विनियमित किया जाता है। सुशासन शासन की प्रक्रिया में एक मानक या मूल्यांकनात्मक विशेषता जोड़ता है। मानवा धिकारों के दृष्टिकोण से यह मुख्य रूप से उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सार्वजनिक संस्थाएँ सार्वजनिक मामलों का संचालन करती हैं, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करती हैं और मानवाधिकारों की प्राप्ति की गारंटी देती हैं।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

पृथ्वी पर प्लास्टिक का शिकंजा: तोड़ने की बारी हमारी

पौधे लगाने, पानी बचाने और अन्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिये हम काफी बातें करते हैं लेकिन क्या वाकई में हम अपने इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो हमें चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे प्रयास नाकाफी हैं। पर्यावरण के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है प्लास्टिक प्रदूषण। इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना' है, जो इस गंभीर मुद्दे की अहमियत को दर्शाती है। प्लास्टिक बेशक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन अब यही प्लास्टिक हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है। अगर हमने समय रहते प्लास्टिक के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो शायद बहुत देर हो जाएगी।

प्लास्टिक प्रदूषण: एक साइलेंट किलर

प्लास्टिक क्यों है ख़तरनाक?

-अपघटन में सैकड़ों साल: एक प्लास्टिक बैग को गलने में 450 से 1000 साल लगते हैं।

-समुद्रों का दुश्मन: हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, जो लगभग 2,200 एफिल टावर्स के वजन के बराबर है।

-माइक्रोप्लास्टिक का ख़तरा: यह छोटे-छोटे कण हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि हमारे ख़ून में भी पाए जा चुके हैं।

हमारी लापरवाही के परिणाम

-जीव-जंतुओं की मौत: समुद्री कछुए, व्हेल और पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है।

-मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।

हम क्या कर सकते हैं?

प्लास्टिक का उपयोग कम करें

-रीयूज़ेबल बैग और बोतलें इस्तेमाल करें: हर साल 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का उपयोग होता है, जिनमें से अधिकांश एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं।

-सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचें: प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी और कप का विकल्प चुनें।

रीसाइक्लिंग को अपनाएँ

-प्लास्टिक वेस्ट को अलग करें: भारत में केवल 60% प्लास्टिक कचरा ही रीसाइकिल हो पाता है।

-इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करें: प्लास्टिक से टाइल्स, थर्माकोल और अन्य उपयोगी चीजें बनाने की तकनीकें विकसित हो रही हैं।

जागरूकता फैलाएँ

-सोशल मीडिया का उपयोग करें: #BeatPlasticPollution जैसे हैशटैग के साथ अपने अनुभव शेयर करें।

-स्कूल और कम्युनिटी में कार्यक्रम आयोजित करें: नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएँ और स्वच्छता अभियान चलाएँ।

आपका एक कदम, पृथ्वी के लिए वरदान

हम सभी को यह समझना होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण कोई दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाज़े तक पहुँच चुकी है। लेकिन अगर सार्थक पहल की जाए तो इसे रोका जा सकता है! इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, आइए संकल्प लें कि हम अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे। क्योंकि जब सभी मिलकर चलेंगे, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, देवरी। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश दुबे ने लोकमाता देवी अहिल्या के जीवन से जुड़े जनकल्याणकारी कार्यों को साझा किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की जिनमें कु. कीर्ति कोरी बी.ए. प्रथम वर्ष ने प्रथम स्थान, कु. जागृति लोधी बी.ए. प्रथम वर्ष ने द्वितीय एवं कु. महक बहना बी.ए. प्रथम वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉ. कलम सिंह डुडवे, शिवलाल अहिरवार, भगवत सिंह पटेल, धर्मेन्द्र अलावा एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इतना बेबस है कि कर्नल सौफिया और सेना का मजाक बनाने वाले नेताओं पर नहीं ले पाया कोई एक्शन?

-विजया पाठक

खुद को जनता का हितैषी और जनकल्याण के लिए समर्पित राजनैतिक पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। देश की आन-बान और सेना की अस्मत कर्नल सौफिया कुरैशी पर अभद्रजनक टिप्पणी करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह की इस अभद्रता पर उनसे इस्तीफा लेने के बजाय उन्हें गुपचुप ढंग से संरक्षण देने का काम कर रही है। यही नहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा खुद देश की शान सेना के जवानों को प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में नत्मस्तक होने की बात कह रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपना सुझाव खो चुकी तमाम महिलाओं को कमजोर बताते हुए बिगड़ैल बयानबाजी की है। सवाल यह है कि क्या भाजपा नेतृत्व इतना बेबस हो गया है कि अपने नेता, मंत्रियों और सांसदों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यही नहीं जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शाह से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि वीडी शर्मा विजय शाह जैसे बिगड़ैल बोल बोलने वाले मंत्री को मंत्री पद से और पार्टी से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। इतने समय के बाद भी अभी तक शाह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं, दूसरी तरफ गरीब किसानों के हित में आवाज उठाने वाले विधायक चिंतामणि मालवीय को पार्टी के नियमों का उल्लंघन बताकर कारण बताओ नोटिस थमा दिया जा रहा है।

पार्टी की मर्यादा को किया शर्मसार

देखा जाये तो भाजपा नेताओं द्वारा दिये गये इन अभद्र बयानों ने न सिर्फ पार्टी की छवि को धूमिल किया है, बल्कि पार्टी की मर्यादा को शर्मसार किया है। यही नहीं बेलगाम बयानबाजी की पहचान रखने वाले मंत्री विजय शाह, जगदीश देवड़ा और सांसद रामचंद्र रामचंद्र जांगड़ा ने स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे राजनेताओं के मूल्यों को तार-तार कर दिया है। इन नेताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज पूरे देश में और विदेश में मध्यप्रदेश की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर को भी करना चाहिए बर्खास्त

आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय महू में आयोजित कार्यक्रम में विजय शाह सेना के शौर्य को शर्मसार करने वाला बयान दे रहे थे। उस समय बाजू में कुर्सी में बैठी पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर तालियां बजा रही थीं। उन्होंने एक बार फिर शाह के इस बयान पर आपत्ति नहीं लेने का विचार नहीं किया और महिला सेना अधिकारी की शर्मसार होती वीरता पर बेशर्मी की तरह तालियां ठोकती रहीं। नियमानुसार पार्टी को तत्काल प्रभाव से ऊषा ठाकुर को भी निलंबित करना चाहिए।

आखिर कसूर क्या है विधायक मालवीय का?

देखा जाये तो चिंतामणी मालवीय अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर उनका कोई दोष है तो वह यह कि वे उज्जैन संभाग के अलीट विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनके सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े रहते हैं। ऐसे में विधायक मालवीय उज्जैन की जनता के साथ किसी भी तरह का गलत होते देख चुप नहीं बैठते और तुरंत जनता के हित में लड़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसे में मालवीय की लोकप्रियता बढ़ती देख न सिर्फ मोहन यादव बल्कि उज्जैन के अन्य नेता भी दंग रह गये हैं। यही कारण है कि वे मुख्यमंत्री यादव के साथ मिलकर चिंतामणी मालवीय के खिलाफ मंत्रणा करते दिखाई पड़ते रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया कि मालवीय का कसूर क्या है। जबकि महिला सेना के अफसरों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्रियों को अभयदान दिया जा रहा है।

इसलिए मुख्यमंत्री की आंख में खटक रहे मालवीय

दरअसल विधायक मालवीय ने पिछले दिनों विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उन्होंने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण, किसानों की भूमि के स्थायी अधिग्रहण और कॉलोनाइजर्स व भू-माफियाओं की साजिश का मुद्दा उठाया था। उन्होंने किसानों की भूमि का स्थाई अधिग्रहण व सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थाई निर्माण पर जनता की आवाज से सरकार को अवगत करवाया था। डॉ. मालवीय की मजबूत आवाज से किसानों में उत्साह देखा गया। उनके उज्जैन आगमन पर किसान आंदोलन समिति ने भव्य स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। यही कारण है कि चिंतामणी मालवीय आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आंखों के कांटे के रूप में खटक रहे हैं।

अपने हक के लिये किसके पास जायेगी जनता

लोकतंत्र में हर विधायक और सांसद को अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए काम करने और निर्णय लेने का अधिकार है। यही कारण है कि जनता जब भी परेशान होती है तो वह अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद के पास जाकर उस समस्या का निराकरण कराने की गुहार लगाती है। ऐसे में चिंतामणि मालवीय ने भी वही किया जो एक विधायक को करना चाहिए था। उन्होंने अपने विधानसभा और जिले के किसान भाईयों के साथ हो रहे धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई जिसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आदिवासी वर्ग को मजबूती देने के लिये उठाये थे महत्वपूर्ण कदम

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में आदिवासी वर्ग के लिये जो कहा उसे न सिर्फ पूरा किया बल्कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आदिवासियों को उस योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे उसकी चिंता करते हुए लगातार प्रयास किये। वहीं उसके उलट प्रदेश की डॉ. मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल की बात करें तो इसमें सबकुछ अलग दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज आये दिन आदिवासी महिलाओं, बहनों के साथ दुराचार, बलात्कार, छेड़छाड़, लूट और मारकाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। जनजातीय वर्ग के साथ लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं न सिर्फ चिंता का कारण है बल्कि यह प्रदेश सरकार की खस्ताहाल कानून व्यवस्था की ओर भी इशारा करती है।

खंडवा की घटना ने किया शर्मसार

मध्यप्रदेश में आज आदिवासी समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि वे खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों खंडवा में आदिवासी महिला के साथ हुई दरिंदगी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्ग आज भी सुरक्षित नहीं है। यह असुरक्षा का भाव न केवल प्रदेश सरकार की नाकामी को जाहिर करता है बल्कि यह प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की असफलता को भी दर्शाता है।

इससे पहले भी हो चुकी हैं आदिवासियों के साथ घटनाएं

इससे पूर्व कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना में सहरिया आदिवासी महिला रामप्यारी बाई को एक जमीन विवाद में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यही नहीं मध्यप्रदेश के मऊगंज जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसा गड़रा गांव में आदिवासी कोल समाज के एक परिवार के ऊपर जानलेवा हत्या की कोशिश की। प्रदेश के आदिवासियों पर हो रहे यह इस तरह के अत्याचार चिंता का कारण हैं। जिस प्रकार से दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें प्रदेश तीसरे नंबर पर आ चुका है। मण्डला की घटना के बाद जवाब आया था कि यदि वे नक्सली नहीं हैं तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कमलनाथ ने साधा भाजपा और मुख्यमंत्री पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में आदिवासियों की जमीनें भू-माफिया द्वारा हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को खुला पत्र लिखकर न केवल भू-माफियाओं पर निशाना साधा, बल्कि जिला प्रशासन पर भी सीधे-सीधे मिलीभगत के आरोप जड़ दिए। कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल जिला है, जहां जामई, तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा, बिछुआ और पांढुर्ना जैसे क्षेत्र आदिवासी संस्कृति की पहचान हैं, लेकिन अब इन क्षेत्रों में संगठित भू-माफिया नेटवर्क सक्रिय हो चुका है, जो आदिवासियों की जमीनें औने-पौने दाम में खरीदने, फर्जी अनुबंध कराने और बाद में नामांतरण कराकर उन्हें गैर-आदिवासियों के नाम दर्ज कराने में जुटा है। कमलनाथ ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में प्रशासन की चुप्पी यह संकेत देती है कि या तो प्रशासन मूकदर्शक है या फिर इस साजिश में सहभागी।

वन अधिकार कानून लाने का श्रेय कमलनाथ को जाता है

मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला किया है। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में चुपीए सरकार में लागू वन अधिकार कानून को लागू करने का फैसला किया। कमलनाथ का यह फैसला आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने और उनके दावों पर विचार करने के लिये आवश्यक था। जाहिर है कि इस कानून का लाभ प्रदेश की 21 फीसदी आदिवासी आबादी को मिला। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों के जमीन संबंधी उन दावों पर फिर से विचार कर उन्हें संबल दिया जिन्हें शिवराज सरकार के दौरान रद्द कर दिया गया था। अपनी योजना के तहत कमलनाथ सरकार ने सवा तीन लाख दावों पर दोबारा विचार किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने वरिष्ठ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उच्च विचारों वालों से सीखना चाहिए जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष के नेताओं से सलाह लेकर लोगों के कल्याण की योजनाओं को बनाते थे और उन्हें लागू करते थे। आखिर लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में कैसी राजनीति करना।

कमलनाथ सरकार ने तैयार किया था वन मित्र सॉफ्टवेयर

कमलनाथ सरकार में इसके लिए वन मित्र सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। इसके जरिए आदिवासी दोबारा दावा कर सकेंगे। इसके लिए आदिवासी इलाकों में वन रक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो आदिवासियों के दावों से जुड़ी जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे। इसके लिए वन रक्षकों को सरकार कुछ राशि का भुगतान करेगी। सरकार की कोशिश थी कि वनक्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन का अधिकार दिया जाए। सरकार का दावा था कि मार्च 2020 तक सभी दावों पर विचार कर आदिवासियों को जमीन का अधिकार दे दिया जाएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)